(b) whether Government are also aware of a large number of deaths caused by Celphos poisoning in the eastern parts of Uttar Pradesh,

(c) if so, what steps have been taken by Government for banning the use of this dreaded poison in view of its dreaded effects;

(d) whether Government would use alternative to Celphos tablets for the preservations of foodgrains;

(e) if so, what are the details thereof; and

(f) whether Government propose to use PARAD tablets for preservation of foodgrains in place of Celphos which are made by Jhandu Pharmacy and are harmless?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI UPENDRA NATH VERMA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The information is being collected from the State Government of Uttar Pradesh.

(d) and (e) Celphos, is the brand name of Aluminium Phosphide the alternatives of which, registered/approved for use in the country are as under:—

(i) Methyl bromide;

(ii) Ethylene dibromide;

(iii) Methyl bromide, + Ethylene dibromide (3:1 and 1:1); and

(iv) Ethylene dichloride-carbon tetrachloride (3:1).

(f) No, Sir.

चीनी का उत्पादन

565. **श्री राम जेठमलानी :**

डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

श्री राम नरेश यादव :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिए जाने सम्बन्धी कोई नई नीति बनाई है, यदि हां, तो क्या दो चीनी मिलों के बीच की दूरी को कम कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि कई सरकारी तथा गैर-सरकारी सोसाइटियों का यह मत है कि चीनी मिलों की रुग्णता का कारण चीनी मिलों के बीच दूरी का कम होना है ;

(ग) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति तक 122 लाख मीटरी टन की उत्पादन क्षमता रखने वाली चीनी मिलों की स्थापना करने के लिए लाइसेंस जारी किए गये थे ;

(घ) क्या यह सच है कि चीनी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई चीनी मिलों के स्थापित किये जाने हेतु हाल ही में लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो नये लाइसेंस के जारी किये जाने के बाद चीनी उद्योग की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी ;

(च) क्या सरकार ने देश में गन्ने के उत्पादन और उसकी उपलब्धता को ध्यान में रखा ; यदि हां, तो चीनी उद्योग को गन्ने का कितना वार्षिक उत्पादन उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ;

(छ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में चीनी उत्पादन की कुल क्षमता कितनी थी; और

(ज) नई चीनी मिलों की स्थापना पर अनुमानत: कितना निवेश किया जाना है और इस निवेश के किन-किन स्रोतों से उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) केन्द्र सरकार नई चीनी लाइसेंस नीति बना रही है जिसकी घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी।

(ख) केन्द्र सरकार (खाद्य विभाग) की दो शीर्ष निकायों अर्थात् भारतीय चीनी मिल संघ और राष्ट्रीय सहकारी चीनी फैक्ट्री परिसंघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि चीनी मिलों की रुग्णता का एक कारण चीनी मिलों की आपस की दूरी का कम होना है।

(ग) से (ङ) 31-3-90 तक नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए जो आशय-पत्र/लाइसेंस जारी किए गए हैं उससे कुल वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता 149.872 लाख टन हो जाएगी। इनमें हाल में ही दिए गए लाइसेंस भी शामिल हैं।

(च) जी हां, चीनी उद्योग के लिए विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए गठित समिति ने अनुमान लगाया था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक गन्ने का उत्पादन 263 मिलियन टन होगा जिसमें से 311 50 मिलियन टन गन्ना चीनी उद्योग के लिए उपलब्ध होगा।

(छ) 31-3-90 तक संस्थापित वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता 91.652 लाख टन थी।

(ज) 31-3-90 तक लाइसेंस दी गई नई चीनी फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए लगभग 2262 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है जोकि (1) किसानों (2) राज्य सरकारों (3) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (4) प्रतर्वकों और (5) केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं से उपलब्ध होगा।

शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध

566. डा० जितेन्द्र कुमार जैन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अप्रैल, 1990 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्टेट्स अनविलिंग टू प्रेहिबिट लिकर सेल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी पत्र है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में, विशेष रूप से संघ राज्य क्षेत्रों में शराब की बिक्री में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष शराब की कितनी बिक्री हुई ;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान लोगों की शराब पीने की लत को छुड़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाये गये ; और

(ङ) उठाये गये ऐसे कदमों पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

Mal-Functioning of cooperative institutions in Punjab

567. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state·

(a) whether the farmers of Punjab have warned Government about the corruption and mal-functioning of co-operative institutions in the State; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI UPENDRA NATH VERMA): (a) According to the information supplied by Punjab Government, no such warning has been received by the State Government about the corruption and mal-functioning of cooperative institutions in the State. However, from time to time when any complaint is received about corruption or mal-functioning of co-operative institutions, it is duly enquired into and appropriate action taken by the State Government.